

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 04, मंगलवार, शाके 1946-जून 25, 2024 Asadha 04, Tuesday, Saka 1946- June 25, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर

अधिसूचना

डूंगरपुर, मई 22, 2024

(भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

संख्या 7404327 :-भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 150 राज 0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा ग्राम वमासा माही नदी पर SH-32 किमी. 218(लसाड़ाब्रिज) मे ब्रिजनिर्माणकार्य मे निम्नानुसार प्रभावित गाँवों मे भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम वमासा विवरण

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा (हे.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)	किस्म
1	मीर पत्नी शंकर, शंकर पुत्र देवा जाति भील सा.देह खातेदार	3576/1358	0.809 हे.	0.2914 हे.	सुखी तृ.
2	जितेंद्र कुंवर पुत्री भारतसिंह नरपतसिंह पुत्र भारतसिंह, राजेंद्रसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपुत सा.देह खातेदार	3598/1358	0.6472 हे.	0.3236 हे.	सुखी तृ.
3	कान्तापत्नी देवराम, नारायण पुत्र देवराम जाति ब्राह्मण सा. पिंडवाल	1359	0.2507 हे.	0.1298 हे.	सुखी द्वि.
4	कान्तापत्नी देवराम, नारायण पुत्र देवराम जाति ब्राह्मण सा. पिंडवाल	1374	0.3802 हे.	0.1456 हे.	सुखी द्वि.
5	अमृत पत्नी स्व. गौतम, ऊकार पुत्र लालजी, खेमजी, भेरा, वेला पुत्र गौतम जाति जोगी सा. देह खातेदार	1360	0.2184 हे.	0.2507 हे.	सुखी द्वि.

6	अमृत पत्नी स्व. गौत, ऊकार पुत्र लालजी, खेमजी, भेरा, वेला पुत्र गौतम जाति जोगी सा. देह खातेदार	1362	0.2265 हे.	0.0728 हे.	सुखी द्वि.
		योग	2.532 हे.	1.2139 हे.	

- अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30-2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सागवाड़ा व उसके स्टाफ कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने व परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सागवाड़ा द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जाएगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
 1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसकी कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जनसुनवाई के दौरान आए सुझावों आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में संबन्धित पंचायत नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शूल्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है।

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।